UKG-27

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - II)

GENERAL STUDIES (Test - II)

मॉड्यूल - II / Module - II

DTVF/17–M–**GS2**

निर्धारित समय: तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	*अधिकतम अंक: 250* *Maximum Marks: 250*

नाम (Name): Sakshi Garg

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? हाँ ✓ नहीं

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनाक (Test No. & Date):

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2017] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2017]:

0	1	4	7	9	0	1

परीक्षा का माध्यम
(Medium of Exam.):

विद्यार्थी के हस्ताक्षर
(Student's Signature):

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

Criterion	Grade
Introduction	B
Context	B
Language	C
Content	C+
Conclusion	B
Structure	B
Current Link / Examples	—

MARKS: 50½ /250

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

व्यापक विश्लेषण / Macro Analysis

- सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।
- विषय-वस्तु को और उन्नत करें।
-
-

Grade Card	
Grade 'A'	Very Good
Grade 'B'	Good
Grade 'C'	Satisfactory
Grade 'D'	Poor

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

1. "भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है।" उपर्युक्त कथन का 'पेड-न्यूज़' की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिये। (250 शब्द) 12.5

"The fourth pillar of Indian democracy is now being guided by commercial considerations rather than pursuit of truth". Critically examine the above statement in the background of paid news and also add your suggestions in reference with the Representation of the People's Act, 1951. (250 words) 12.5

Ans भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत संरचना में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ-साथ चौथा महत्वपूर्ण स्तम्भ है 'मीडिया'। परन्तु वर्तमान में पेडन्यूज, पीतपत्रकारिता आदि के कारण यह संदेह के घेरे में है।

पेड न्यूज के अन्तर्गत मीडिया द्वारा न्यूज का प्रसारण निष्पक्षता, यथास्थिति न होकर किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में होता है। अर्थात् पैसे के बल पर समाचार को मनवांछित रूप दिया जाता है।

- पेडन्यूज से मीडिया की निष्पक्षता पर संदेह किया जाता है।

- वस्तुतः मीडिया जनता की मानसिकता को रूप देने में बड़ी भूमिका निभाती है, परन्तु किसी ~~व्यक्ति~~ विशेष ~~पार्टी~~ विशेष के पक्ष में समाचार प्रसारण से लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है।

समस्याएँ एवं परिणामों की और स्पष्ट चर्चा करें!

- मीडिया के द्वारा व्यवसायिक हितों के लिए पीतपत्रकारिता,

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

पेड-न्यूज, मीडिया ट्रायल आदि के कारण लोकतंत्र की वास्तविक अभिव्यक्ति को मलिन कर रही है।

- यह संवैधानिक उल्लंघन है क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गयी है, जिसका दुरुपयोग करना अपराधनीय है।

- यद्यपि तमाम आलोचनाओं के बावजूद मीडिया की अपनी विशिष्ट भूमिका है। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आज भी मीडिया द्वारा जनहित के मुद्दों पर जनता को जागरूक करने, सरकार पर नैतिक दबाव डालने, लोकतंत्र को दशा व दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। उदाहरण-स्वरूप - निर्भया काण्ड, भ्रष्टाचार उजागर करना, स्टिंग ऑपरेशन कर अपराधी को बेनकाब करना।

यद्यपि पेड-न्यूज, व्यवसायिता जैसी शिकायतों हेतु उचित कानूनी प्रावधान लाने आवश्यक है, साथ ही मीडिया को स्वयं आगे बढ़कर अपनी ईमानदार छवि हेतु प्रयास करना चाहिए। इसी में देशहित व देश लोकतंत्र सार्थक हो सकेगा।

· लोकपाल की नियुक्ति
· सिविल सोसायटी की भूमिका को सशक्त करना

Copyright – Drishti The Vision Foundation

· पत्रकार की स्वतंत्रता आदि सुझावों की अस्पष्ट चर्चा करें।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 → चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रभावी व वास्तविक लोकतंत्र हेतु इस कानून में कुछ सुधार की आवश्यकता है

- नेताओं द्वारा धर्म, जाति के आधार पर वोट मांगने को आपराधिक ठहराया जाए
- बूथ कैप्चरिंग, बल, धन प्रयोग के आधार पर चुनाव निरस्त करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को दी जाए। अभी अनुच्छेद 326 के तहत वह ऐसा करता है।
- चुनाव प्रक्रिया में धन बल प्रयोग कम करने हेतु स्टेट फंडिंग की जाए।
- दो जगह से चुनाव लड़ना असंवैधानिक किया जाना चाहिए
- चुनाव में बड़ी मात्रा में लोकलुभावन नीतियों की घोषणा को तार्किक व मितव्ययी बनाया जाए।

निष्कर्ष ?

(3)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1½	1	0.25			
Grade	B	C	C	C			

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

2. यद्यपि भारत 'ब्राज़ील घोषणापत्र' का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, फिर भी यहाँ सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय संकट कहा जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Though India is a signatory to 'Brasilia Declaration', the road accidents can be termed as national crisis, illustrate. Examine the Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2016. (250 words) 12.5

Ans ब्राजील घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद भारत में तीसरी सबसे बड़ी संख्या में होने वाली मौत का कारण सड़क दुर्घटना है।

आंकड़ो के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2.6 करोड़ लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। 5 करोड़ लोग घायल या किसी शारीरिक विकलांगता का शिकार हो जाते हैं।

सबसे बड़ी चिन्ता की बात है कि मरने वालों में 35% जनसंख्या 15-35 वर्ष की आयु की मध्य की है, जो भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश है।

इस परिप्रेक्ष्य में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016, लाया गया है-

लाभ-

- सड़कों पर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा तथा इसकी जिम्मेदारी अवसंरचना निर्माणकर्ता की होगी।

संक्षेप में ब्रासिलिया घोषणा-पत्र क्या है, स्पष्ट करें

अन्य कारणों को बताएं

तथ्यों की जांच कर लें।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

- सड़कों पर जेबराक्रॉसिंग व किनारे पथचालक बनाना अनिवार्य किया गया।

- सड़कों पर भीड़भाड़ कमकरने हेतु ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग पर बल दिया गया

- ब्राजील घोषणापत्र के तर्ज पर ही वैश्विक मानकों के अनुरूप गाइडलाइन्स जारी की गयी।

कमियां >

- वित्त व्यवस्था के बारे में अस्पष्टता

- भाषा अस्पष्ट व सीमित परिभाषा

- जवाबदेहिता तय करने व उचित SOS की व्यवस्था का अभाव

- हाइवे आदि पर मादक बिक्री पर रोक का अभाव

वस्तुतः सरकार द्वारा लाया गया बिल जनहित में है बड़े संकट को दूर करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। तथापि इसे और तार्किक बनाने हेतु देश संवैधानिक मूल्यों, 'जीवन के अधिकार' का वास्तविकता में बदला जा सकता है।

(Examiner's margin notes: ग्राफ छात्रों की स्पष्ट चर्चा करें। जैसे — • थर्ड पार्टी इंश्योरेंस • टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन • मोटर यान दुर्घटना की निधि आदि। · ओवरस्पीडिंग की समस्या · सड़क सुरक्षा अधिकरण के स्थापना की चर्चा नहीं "" को लिखें। 2½)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	0.5	0.25	×	0.25	<
Grade	D	C	D	C		D	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

3. हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? इसके विवादित पक्षों पर प्रकाश डालिये तथा भारतीय सिनेमा की समग्रता तथा भारत की विशिष्ट संस्कृति के संबंध में अपने सुझाव दीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recently censor board of India was in news for pre censorship of films. Is pre censorship violates copyrights and fundamental rights. Highlight the areas of controversy and put your suggestions for integrity of Indian cinema and ethnicity of Indian culture. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Ans भारतीय फिल्म प्रमाणिकरण बोर्ड हाल में उड़ता पंजाब, कडप्पा जैसी विवादित फिल्मों की पूर्व सेंसरशिप को लेकर चर्चा में रहा, वस्तुतः पुनः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सेंसरशिप पर विवाद शुरु हो गया है। इस प्रकार पक्ष-विपक्ष के आधार पर विश्लेषण करना होगा –

संक्षेप में भारत में सेंसरशिप की शुरुआत की चर्चा करें।

कॉपीराइट व मौलिक अधिकारों का उल्लंघन –

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के आधार पर डाइरेक्टर के अधिकार का उल्लंघन है।

और स्पष्ट चर्चा करें।

- वस्तुतः भारतीय पेटेंट पॉलिसी 2016 के आधार पर कॉपीराइट का अधिकार प्रदान किया गया है, जो इस निर्णय से सामंजस्य नहीं रखता।

- सेंसर बोर्ड स्वयं राजनैतिक दृष्टिकोण से कई बार प्रभावित

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

रहा है, साथ ही फिल्म प्रमाणीकरण से ज्यादा छटनी की भूमिका निभा रहा है।

- भारत विभिन्न धर्म, जाति, वर्ग, भाषा के लोगों का समूह है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा - "यदि कोई चीज आपको अपने धर्म के प्रतिकूल लगती है तो आप उसे न देखें।"

उत्तर लेखन में तारतम्यता रखें।

विपक्ष →

- यद्यपि देश की अखण्डता व शांति को बनाए रखने हेतु समय-समय पर सेंसरशिप अनिवार्य है।

- हाल में दिखायी जा रही नग्नता का नयीपीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अपराधीकरण को रोकने हेतु तार्किक सेंसरशिप अनिवार्य है।

- संविधान द्वारा अभिव्यक्ति पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 19(2) में किया गया है।

प्री-सेंसरशिप के नाम पर फिल्मकारों की रचनात्मकता को बाधित... कुछ फिल्मों के प्रिंट का लीक होना आदि जैसे बिन्दुओं को लिखें

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

सुझाव →

- भारतीय मीडिया को स्वयं आचार संहिता लागू करनी चाहिए व फिल्म निर्माण के समय देश की विविधता, आस्था व देश की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।

- फिल्म सेंसर बोर्ड में राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हो
- फिल्म सेंसर बोर्ड को तीन कोटियों A, A/U, U के आधार पर फिल्मों का वर्गीकरण कर देना चाहिए।

- भारतीय जनता को सहिष्णुता का परिचय देते हुए फिल्मों को देखें, साथ ही वे आधुनिक परम्पराएं जो अंधविश्वासों, रूढ़ियों से तारतम्य नहीं रखतीं उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें।

इस प्रकार फिल्मों की वास्तविक प्रासंगिकता सिद्ध हो सकेगी, जो हमारे देश की संस्कृति मनोदशा, चरित्र व भविष्य का प्रतिबिम्ब करती है।

3½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1½	1	0.25	✗	0.25	✗
Grade	B	C	C	C	✗	B	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

4. "संविधान संसद को शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है तथा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।" इस कथन को पृष्ठभूमि में रखते हुए क्या आप सोंचते हैं कि संसद के कामकाजे के नियंत्रण तथा इसे सुगम बनाने के लिये एक निगरानी आयोग की आवश्यकता समय की मांग है? (250 शब्द) 12.5

"The Constitution provides powers and immunities to the Parliament and the Parliament can amend the Constitution". In the background of above statement, do you think a monitoring commission is the need of the hour to control and facilitate the functioning of the Parliament? (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Ans संविधान के अनुच्छेद 105 व 194 के तहत संसद व विधानसभा को विशेष उन्मुक्तियां प्रदान की गयी हैं, जहां उन्हें कार्य दिवस में दिए गए बयान की गयी अपराधिक गतिविधियों के लिए कई उन्मुक्ति प्रदान की गयी है।

संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संसद को साधारण बहुमत, विशेष बहुमत व विशेष + आधे से अधिक राज्यों के वोट से बहुमत की शक्ति प्रदान की गयी है।

हाल में सांसदों द्वारा की जा रही मनमानी, अनैतिक कार्यवाही, भ्रष्टाचार आदि ने आधार पर निगरानी आयोग की व्यवस्था की मांग उठ रही है —

व्यक्तिगत एवं सामूहिक विशेषाधिकारों की स्पष्ट चर्चा करें।

व्यक्तिगत
बोलने की स्वतंत्रता

सामूहिक
अवमानना के लिए दंडित करने
चर्चा को प्रकाशित करने।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

निगरानी आयोग की आवश्यकता—

- सांसदों पर नैतिक दबाव डालेगा ताकि वे मर्यादित व्यवहार करें। उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा।
- संसद में पक्ष व विपक्ष की वास्तविक मंशा को सार्थक रूप देगा।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आम जनता, रिपोर्टर पर की जा रही दमनात्मक कार्यवाही पर लगाम लगेगी।
- बिना चर्चा-परिचर्चा के बिल पास नहीं होगा

यद्यपि सांसद जैसे गरिमामयी पद को कानून या आयोग के आधार पर मर्यादित करना अतार्किक प्रतीत होता है। निगरानी आयोग सांसदों पर एक सीमा तक ही दबाव बना सकता है, हमें इससे आगे बढ़ते हुए अन्य उपाय करने की आवश्यकता है—

- सांसदों हेतु एक आचार संहिता बनायी जाए।
- ~~स्वयं सांसद आगे बढ़कर~~ उनके द्वारा संसद में की जारी रही कार्यवाही को जन-जन तक प्रसारित किया जाए ताकि मतदाताओं का नैतिक दबाव पड़े।

संविधान द्वारा किए गए एक उपायों की चर्चा करें।
· बजट
· संसदीय समितियाँ
· वित्त के ऊपर नियंत्रण आदि।
तक उपायों का उल्लेख करें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

- सांसदों को स्वयं आगे बढ़ते हुए अपनी मर्यादा, बड़प्पन का परिचय देना चाहिए।

वस्तुतः हमारा देश सीरिया व ईराक जैसा नहीं अपितु, संवैधानिक, मूल्य, परम्पराओं व सवा अरब जनआकांक्षाओं पर टिका है; जिसमें सांसद स्वयं आपसी सहमति से समस्या समाधान करने में सार्थक है।

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	1	0.25	×	0.25	×
Grade	B	C	C	B	×	B	×

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

5. कुछ राज्यों और क्षेत्रों को प्राप्त विशेष दर्जा अधिक जनांदोलनों को भड़काने का काम करता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

The special status to some states and certain regions provoke more mass agitation. Critically examine. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Ans → राज्य विशेष को विशेष दर्जा देने की नीति ने दोधारी तलवार की तरह काम किया है, एक ओर असमान को रियायत देने का प्रयास तो दूसरी ओर इसने जनांदोलनों को भड़काने में उत्प्रेरक का काम किया।

- विशेष दर्जा देने से अन्य राज्य भी इसी तरह की मांग करने लगते हैं।

- यह एक वोट बैंक राजनीतिक हथियार बन गया है जिसकी प्रतिलिपि बिहार में देखी जा सकती है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार विशेष दर्जा प्राप्त राज्य अपने संसाधनों का पूर्णतः उपयोग न कर पाने के कारण पिछड़ गए हैं, जो सामाजिक अराजकता, जनान्दोलनों का बड़ा कारण है।

- केन्द्र व राज्य में विभिन्न दल की सरकार होने पर

विशेष दर्जा दिये जाने के उद्देश्यों को लिखें।

· अलगाववाद
· क्षेत्रवाद
· उग्रवाद
आदि की ओर स्पष्ट चर्चा करें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

इन आन्दोलनों को और बढ़ावा मिलता है।

यद्यपि विशेष दर्जा देने के कुछ सकारात्मक पक्ष भी है -

- विकास की दौड़ में पीछे छूट गए राज्यों को कुछ रियायत देना।

- संवैधानिक मूल्य समानता व सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक न्याय की प्राप्ति

- इतिहास में हुए भेदभाव की क्षतिपूर्ति

अन्य सकारात्मक पक्षों को भी लिखें।

केन्द्रीय सहायता का बड़ा हिस्सा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को।

विश्लेषण करने व आर्थिक समीक्षा द्वारा दिए आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो विशेष दर्जा से आगे बढ़ कर हमें अन्य दिशा में सोचना होगा -

- नीति आयोग की सिफारिशों अनुसार सहकारी संघवाद व प्रतिस्पर्धी संघवाद की नीति अपनानी होगी।

- राज्य को मात्र कठिन मानने के बजाए ऐसे प्रयास करने चाहिए कि अपने भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त प्राकृतिक, भौगोलिक व मानवीय संसाधनों का इस्तेमाल

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

प्रयोग कर सकें।

इस आधार पर देश में समानता की प्राप्ति की लक्ष्य पूरा हो सकेगा जो संवैधानिक मूल्यों के साथ-साथ, केन्द्रीय राजकोष व राष्ट्रहित में होगा।

4½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2	1½	0.25	×	0.25	×
Grade	B	B	C	B	×	B	×

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. (a) आम लोगों को त्वरित न्यायिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन समय की आवश्यकता है? 6

The creation of All India Judicial Services (AIJS) is the need of the hour for providing fast judicial services to the common people. 6

Ans वर्तमान में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर ही "अखिल भारतीय न्यायिक सेवा" की आवश्यकता प्रतीत हो रही है क्योंकि -

- सम्पूर्ण देश में एक पाठ्यक्रम, एक परीक्षा निर्धारित होगी
- राज्य स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद पर लगाम लगेगी।
- न्यायिक भर्ती की प्रक्रिया अविलंब पूरी होगी जिससे त्वरित न्याय प्राप्त होगा (जस्टिस डिले इस जस्टिस डिनाइड)
- देश सम्पूर्ण देश से प्रशासनिक सेवा के तर्ज पर ही होनहार परिक्षार्थियों का चयन सम्भव हो सकता

संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा

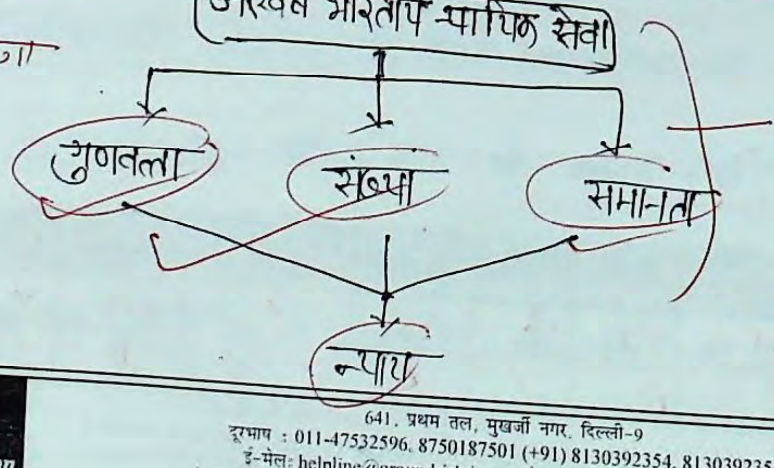

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)
कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

- सम्पूर्ण देश में एक परीक्षा से न्यायिक भर्ती होने पर समानक मानकों पर आधारित न्यायिक प्रक्रिया का निर्माण होगा।

- अलग-अलग राज्यों के अनुसार तैयारी करने के बजाए एक निर्धारित दिशा में तैयारी करने पर परीक्षार्थियों की ऊर्जा बचत होगी।

संपूर्ण प्रक्रिया देश हित में है, इसे जल्द ही लागू किया जाना अपेक्षित है।

चुनौतियों को भी लिखें।

प्रभावी निष्कर्ष लिखें।

1½

(b) क्या आप सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ोतरी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है? चर्चा करें। 6.5

Do you think mushrooming of administrative tribunals is creating a hurdle in judicial processes? Discuss. 6.5

संक्षेप में न्यायाधिकरण को परिभाषित करें।

Ans> तेजी से बढ़ रहे प्रशासनिक न्यायाधिकरण कई समस्या उत्पन्न कर रहे हैं — न्याय में देरी
- मुद्दों की ओवरलैपिंग (दोहराव)
- कार्यक्षेत्र की अस्पष्टता
- संसाधनों की फिजूलखर्ची
- भ्रष्टाचार

• पर्याप्त कार्यबल में कमी
• सरकार से स्वतंत्र नहीं
• [illegible]
• गैर-न्यायिक सदस्यों की उपस्थिति आदि का उल्लेख करें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

उदाहरणस्वरूप → सेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल व कंपनी एक्ट 2013 से बना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) इन दोनों के कार्यों में काफी दोहराव है, जिससे न्यायप्रक्रिया में विलम्ब होता है।

- हाल ही में वोडाफोन टैक्स विवाद के परिप्रेक्ष्य में उठे विवाद से पुनः ट्रिब्यूनल की संख्या को तार्किक बनाए जाने की मांग तार्किक प्रतीत होती है।

सुझावों को भी लिखें
↓
• क्षेत्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन

2

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	0.5	0.5	0.25	<	0.25	<
Grade	B	B	B	C	<	B	<

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

7. चुनावों के वित्त पोषण से संबंधित पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में किये गए हालिया उपायों पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये तथा राजनीतिक दलों की बेहतर जवाबदेही के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये? (250 शब्द) 12.5

Critically comment on the recent measures taken to improve transparency in electoral funding and what steps should be taken for better accountability of political parties. (250 words) 12.5

Ans चुनाव प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की पहचान है सरकार ने समय-समय पर इसकी निष्पक्षता के लिए प्रयास किए हैं—

- रिजर्व बैंक ने 2000 से ऊपर के चन्दे के लिए बाण्ड जारी करने को कहा है।
- किसी भी उम्मीदवार को अपने साथ-साथ संपूर्ण परिवार (रक्त संबंध) की सम्पत्ति की घोषणा करनी होगी।
- वे राजनीतिक पार्टियां जो चंदा तो लेती हैं, पर चुनाव नही लड़तीं उन पर लगाम लगायी जाएगी।
- निजी यात्राओं को छोड़ शेष सभी खर्च, चुनाव खर्च में ही जोड़े जाएंगे।
- चुनाव में खर्च की जा सकने वाली राशि को सीमित करने के साथ-साथ डिजिटलाइज्ड किया गया।

चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता आवश्यक क्यों? स्पष्ट करें

अन्य सुधारों को लिखें
↓
चुनावी बांड जारी करने का प्रस्ताव

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

वस्तुतः तमाम सुधारों के बावजूद अभी भी अनेक कमियां हैं —

— बॉण्ड जारी करने वाली कंपनियों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, जो पुनः काले धन का स्रोत है।

— राजनीति के अपराधीकरण पर रोक होनी चाहिए।

— चुनावों को ब्रिटेन के तर्ज पर भारी भरकम बनाने के बजाय साधारण बनाया जाना चाहिए था।

सुझाव →

— इन्द्रजीत गुप्ता समिति के तर्ज पर स्टेट फंडिंग को बढ़ावा दिया जाए। जिससे राजनीति का लोकतांत्रिकरण हो सके।

— जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अपेक्षित सुधार कर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, तार्किक बनाया जाए।

— चुनाव आयोग को और शक्तिशाली बनाया जाए।

— पेड न्यूज, शैल कंपनी, काला धन पर लगाम लगाना। अन्यथा तरीके से चुनाव सुधार किया जा सकता है।

'कुल नगदी प्राप्ती कोई ऊपरी सीमा नहीं
· RTI के दायरे में नहीं आदि की चर्चा करें।
·कारपोरेट प्रभाव को कम करें
·RTI के दायरे में लाना
विदेशी धन संबंधी अधिनियम को कठोरता से लागू करना

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

वस्तुतः एक निष्पक्ष, समानता आधारित तार्किक चुनाव प्रक्रिया ही राष्ट्र हित में होगी व लोकतंत्र को और मजबूत करेगी।

7

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2	1	0.25	×	0.25	×
Grade	A	B	C	E	×	B	×

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

8. यह देखा गया है कि काला धन खपाने के लिये अचल संपत्ति मुख्य क्षेत्रों में से एक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि कैसे हाल ही में लागू किये गए अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम (RERA) से भ्रष्टाचार को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी? (250 शब्द) 12.5

It is observed that real estate is one of the main domains of placing black money. Critically analyze that how recently adopted RERA (Real Estate Regulation and Development Act) will help in curbing corruption and protecting consumer rights. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

Ans → काला धन अर्थात् समानान्तर अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है - सोना, रियल स्टेट, जमीन। इसके आधार पर आसानी से कर चोरी की जा रही है।

इसकी ~~सबसे~~ पुष्टि आंकड़ो से होती है - हमारे देश में मात्र 4% लोग टैक्स देते हैं और मात्र 0.1% लोग ऐसे हैं जो अपनी आय 1 करोड़ से ज्यादा बताते हैं।

1/2

उत्तर अपूर्ण है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks			05				
Grade			D				

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

9. अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय के नाम पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रभावकारी अधिकार प्रदान करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Article 142 provides Supreme Court a virtual license to intervene in any matter in the name of complete justice. Critically analyze. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Ans→ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक प्रतीत होने पर किसी भी मुद्दे में हस्तक्षेप कर न्याय प्रदान करने का विशेषाधिकार रखता है।

उदाहरणस्वरूप - अनुच्छेद 262 के तहत जल विवाद न्यायाधिकरण में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम माना गया है व सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मनाही है, परन्तु समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वाद में, स्वास्थ्य का अधिकार के आधार पर, समान आचार नागरिक संहिता, लोकपाल अधिनियम आदि वादों में सर्वोच्च न्यायालय की सहभागिता देखी गयी।

यद्यपि संविधान द्वारा प्रदत्त ये अधिकार असीमित न होकर तार्किक व मर्यादा निहित है:—

न्यायिक सक्रियता के उदय की पृष्ठभूमि का उल्लेख करें।

अन्य उदाहरणों को भी लिखें तथा इसके लाभों को भी बताएँ

ताजमहल की सफाई

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा की गयी है कि वह निर्णय लेते समय अपने मर्यादा का ध्यान रखें।

- संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत तीनों स्तम्भों कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का कार्यक्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन की कल्पना की गयी है।

- वस्तुतः न्यायालय संविधान का कस्टोडियन है अतः अन्याय पर लगाम लगाने, कार्यपालिका, विधायिका के उन्मुख रवैय दिखाने पर पर यह न्यायपालिका का ही कर्तव्य होना चाहिए कि वह इन्हें संतुलित करे।

इस प्रकार कहा जा सकता है अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति तार्किक व युक्तियुक्त है।

अन्य नकारात्मक पक्षों को बताएँ। जैसे- निर्णय का स्वेच्छाचारिता में बदलना।

(3)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	1	0.25	1	0.25	1
Grade	B	C	C	C	Y	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

10. एक ऐसा देश जहाँ के अधिकांश नागरिक सरकार की नीतियों तथा सरकार के कामकाज को लेकर अनभिज्ञ हैं, वहीं विभिन्न संवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देना मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

A country in which most of its citizens are unaware of functioning of government and government policies; mandatory Aadhar card link to various services will create a trauma of confusion, analyze. (250 words) 12.5

Ans वर्तमान में सम्पूर्ण आबादी को बायोमीट्रिक पहचान के आधार पर आधार कार्ड से जोड़ना पूरे देश में चर्चा परिचर्चा का विषय बना हुआ है। इस कदम की आलोचकों द्वारा निम्न आधार भी पर आलोचना की जा रही है -

- आधार कार्ड में व्यक्ति की निजी सूचना का संग्रह करना निजता के अधिकार के खिलाफ है।
- जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है।
- संग्रहित सूचना का प्रयोग स्वयं व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है।

→ दुरुपयोग की सम्भावना बढ़ सकती है।

अन्य चिन्ताओं का उल्लेख करें।

वस्तुतः इन आलोचनाओं को इस आधार पर गलत ठहराया जा सकता है कि आलोचना करने वाले अभी आधार कार्ड के पूरे प्रावधानों से परिचित नहीं हैं, साथ ही आधार कार्ड की देश के हित में क्या प्रासंगिकता हो सकती है, उसका उन्हें

आधार रिकार्ड एवं प्रमाणिकरण की समस्या के कारण वास्तविक लाभार्थी बाहर।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अनुमान भी नहीं है –

– आज सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर सरकारी नीतियां सब्सिडी योजना जारी किए जाने के बावजूद लाभ का मात्र 10% लाभार्थी तक पंहुचता है।

– लाभार्थी की सही पहचान न होने, फर्जी कार्ड बनने, आंकड़ों के दोहराव के कारण खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा जैसी योजना अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकीं हैं ⇒ इसके लिए आवश्यक है एक राष्ट्रीय पहचान की।

– इसके साथ ही आधार कार्ड में सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं, इसे दो ही स्थिति में उजागर किया जा सकेगा [राष्ट्रीय हित में / न्यायालय की आज्ञा पर

वस्तुतः आधार कार्ड के प्रति जनता में सुरक्षा की भावना लाने हेतु पर्याप्त रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।

इसके लिए मीडिया

लाभों की और स्पष्ट चर्चा करें

• डिजिटल लॉकर खोलना सम्भव
• वित्तीय समावेशन को बढ़ायेगा
• कर चोरी को रोका जा सकता है।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

न्यूजपेपर, टी० वी० चैनल का सहारा लिया जा सकता है। साथ ही गैर सरकारी संगठनों व सिविल सोसाइटी की भूमिका इस परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है।

3½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1½	1	0.25	X	0.25	X
Grade	B	C	B	C	X	B	X

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

11. हाल ही में महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर एनएसएस के आँकड़ों में प्रदर्शित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। समालोचनात्मक-परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recent NSS data on women labour force participation has shown that women labour participation is stagnated in urban areas and sharply declining in the rural areas. Critically examine. (250 words) 12.5

Ans हाल में जारी एनएसएस के आंकड़ों अनुसार — देश की कुल जनसंख्या का 48% होने के बावजूद महिला श्रम भागीदारी मात्र (23%) है।

यदि गांव व शहर के आधार पर यह आंकड़ा परखें तो शहरों में यह प्रतिशत स्थिर है व गांव में स्थिति और बेकार होती जा रही है।

कारण,

- शहरी क्षेत्र में देखें तो असुरक्षा की भावना, समान वेतन न मिलना, घर व ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी ने महिलाओं को कार्य छोड़ने पर विवश किया है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, जहां असुरक्षित कार्य वातावरण, शौचालय जा, (क्रेच) सुविधा का अभाव, अतिशून्य वेतन, रोजगार असुरक्षा जैसी परिस्थितियां महिला श्रम के आगे बाधा

स्थिरता के कारणों की स्पष्ट चर्चा करें।

• विशेष तकनीक कौशल की आवश्यकता

• स्थानीय स्तर पर रोजगार का न मिलना

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

बन रही है –

परन्तु कुछ ऐसे मुद्दे व आँकड़े हैं जिनके आधार पर स्वास्थ्य का सर्वेक्षण अधूरा प्रतीत होता है –

ग्रामीण क्षेत्रों में ॥ कृषि एवं गैर कृषि कार्यों की उपलब्धता

- ग्रामीण से शहर की ओर प्रवसन के कारण तेजी से कृषि का महिलाकरण हो रहा है। कृषि में 84% महिला कृषक कार्यरत है।

- बढ़ता शिक्षा स्तर, बढ़ रही परिवार की आवश्यकता व नारी आत्मसम्मान की मुहिम ने महिलाओं को अनेक बाधाओं के बावजूद कार्य करने को प्रेरित किया है।

संक्षिप्त लिखें।

यद्यपि किए गए सर्वेक्षण को परिभाषा के आधार पर परखना होगा। NSS द्वारा किया गया सर्वेक्षण संगठित क्षेत्रों तक आधारित है।

सुझावों को लिखें।

- इसके साथ ही महिला कार्य बल का बड़ा प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है।

- महिला कार्यबल जो किसी के घर खाना बनाने, सफाई कार्य या अनुत्पादक कार्यों में लगी है उन्हें

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

न गिने जाने की वजह से इस तरह के आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

~~अतः~~ यद्यपि अभी महिला कार्यबल सहभागिता हेतु बहुत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

भावी निष्कर्ष लिखें।

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	1	0.25	—	0.25	x
Grade	B	C	C	C	—	B	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

12. प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। हाल ही में धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाचार माध्यमों में लगातार उछाला जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कीजिये, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

From ancient times secularism was essential feature of Indian society. Recently the term secularism was flaunted continuously in media news. Analyze the current scenario in this regard; is secularism in India at risk? Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

Ans → यदि प्राचीन काल में दृष्टिपात करें तो कई सौ दशकों तक हिन्दू-मुस्लिम धर्म के साथ-साथ रहने के बावजूद कभी भी धार्मिक ~~अहिष्णु~~ असहिष्णुता, तोड़ फोड़ देखने को नहीं मिलते। उदाहरणस्वरूप सम्पूर्ण मुगलकाल मुस्लिम शासक व बहुसंख्यक हिन्दू जनता के बावजूद सहिष्णुता का परिचायक रहा।

(प्रभावी भूमिका लिखें)

हाल ही में समाचारों में धर्मनिरपेक्षता शब्द बार-बार देखने को मिल रहा है। वर्तमान में मुजफ्फरनगर दंगे, अयोध्या काण्ड, बीफ मुद्दा, गौ हत्या जैसे मुद्दों के कारण यह शब्द पुनः वाद विवाद का विषय है-

(• भीड़ दंड • लाउडस्पीकर जैसे मुद्दे के कारण चर्चा में रहा)

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता खतरे में है-

- वस्तुतः किसी भी दंगे से मुद्दे को राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक राजनीति की तरह प्रयोग किए

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

जाने के कारण धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है।

- मुद्दों को धार्मिक गुरु, मौलवी, पण्डित धर्म से जोड़ रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में है।

वस्तुतः भारतीय समाज सदैव से सहिष्णु, सद्भावनायुक्त व धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक रहा है। आज भी विशाल जनसंख्या के मन में ये संस्कार विद्यमान हैं। यद्यपि कुछ अराजकतावादी तत्व तात्कालिक मुद्दों का धार्मिकीकरण कर अपने हित साधने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर लगाम लगायी जानी चाहिए —

- मीडिया को अपने चतुर्थ स्तम्भ की भूमिका अदा करते हुए आम जनता को दिग्भ्रमित होने से बचाना चाहिए।

- राजनीतिक दल जो वोट बैंक राजनीति के आधार पर अराजकता फैलाते हैं उन पर दण्ड निर्धारित हो।

- इस विषय पर पुलिस कार्यबल को विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, ताकि शांति से मामलों को शुरुआती दौर में निपटाया जा सके।

मीडिया समूह की भूमिकाओं की भी चर्चा करें।

धर्मनिरपेक्षता की वर्तमान स्थिति का भी उल्लेख करें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

- सूफी धर्म, स्कूली पाठ्यक्रम, योगा व जागरूकता के माध्यम से समाज में सहिष्णुता, समरसता का भाव फैलाना चाहिए।

वस्तुतः यही राष्ट्रीय हित में है।

हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति व संस्कारों की नींव इतनी मजबूत है कि इसे पूरी तरह हिलाया नहीं जा सकता। हां, यदि किसी कारण यह दिग्भ्रमित हो रही है तो इसे एक दिशा देने की आवश्यकता है।

3½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1½	1	0.25	—	0.25	
Grade	B	C	C	C	—	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

13. भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर रही है लेकिन किसानों की सुरक्षा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Indian government is focusing on food security of its citizen but farmer's security deteriorating day by day. Critically examine challenges for food security and also mention suggestion for improvement of conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Ans भारत सरकार सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली, काम के बदले अनाज, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड आदि के माध्यम खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

परन्तु दूसरी ओर किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है—

- आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में हर 1 घण्टे में 1 किसान आत्महत्या कर रहा है।
- मानसून अनियमितता, बिचौलिया, बिल की कमी, कम उत्पादकता, पूर्ण मूल्य न मिलने आदि कारणों के कारण कृषि लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गयी है।
- 40% किसान किसी अन्य रोजगार की तलाश में है।
- युवा पीढ़ी का कृषि की ओर कोई आकर्षण नहीं है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां -

- सरकारी योजनाओं का लाभ अपेक्षित, वंचित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा। संपूर्ण फण्ड विचौलिए, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के नाम जा रहा है।

- ग्लोबल हंगर इन्डेक्स में भारत का स्थान 118 देशों में 97 वां है व संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के हर 3 में से 1 कुपोषित बच्चा भारत में है।

- हमारी योजनाएं चावल, गेहूं तक सीमित हैं जबकि अण्डा, दूध, दाल, प्रोटीन, विटामिन अभी भी गायब है।

यद्यपि इस संदर्भ में सरकार द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, और विभिन्न योजनाओं को आधार कार्ड, डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से परिणाम आधारित बनाने की कोशिश की जा रही है।

· खाद्यान्न की निम्न उत्पादकता · भण्डार सुविधा का अभाव · उर्वर कृषि भूमि का स्थानांतरण · व्यवसायीकृत कृषि बैंकिंग का अभाव आदि चुनौतियों का उल्लेख करें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

किसान स्थिति सुधार हेतु उपाय ->

- सर्वप्रथम कृषि को परंपरागत कार्य के आधार पर न देखकर उद्यमिता के आधार पर देखना चाहिए, कॉरपोरेट फार्मिंग व कान्ट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देकर वित्त, अवसंरचना, छोटी जोत आकार, बिचौलिया, प्रसंस्करण व चेन सप्लाई कमी, जोब स्कोप जैसी सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

- सरकारी नीति, योजनाओं को तार्किक बनाए जाने के साथ-साथ किसानों के बीच उसके प्रति पर्याप्त जागरूकता फैलायी जाए। सर्वेक्षणनुसार -67% किसानों को यह तक नहीं पता है कि एम. एस. पी. होता क्या है।

- हरित व जैव कृषि, माइक्रो इरीगेशन, मिश्रित कृषि, जल कृषि आदि को बढ़ावा देकर आय का विविधीकरण किया जा सकेगा।

अन्य उपायों की चर्चा करें।

तथ्यों की जांच कर लें।

निष्कर्ष?

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1/2	1	0.25			
Grade	B	C	C	C			

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

14. भारत में एकल परिवार का प्रचलन संयुक्त परिवार से अधिक होता जा रहा है क्योंकि भारतीय समाज समूह की अपेक्षा व्यक्तिवाद की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Trends of nuclear family in India are more common than joint family as Indian society is heading towards more individualism than community. Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Ans → वर्तमान में भारतीय समाज संयुक्त परिवारों से टूटकर एकल परिवारों की ओर प्रचलित हो रहा है जिसका एक बड़ा कारण है – व्यक्तिवाद की भावना

प्रभावी भूमिका लिखें।

वस्तु व्यक्तिवाद के कारण व्यक्ति के अन्दर स्वार्थ की भावना परम हो जाती है। सम्पूर्ण परिवार की अपेक्षा वह स्वयं की जिम्मेदारी को ही वहन करना चाहता है। इसके साथ ही स्वतन्त्रतायुक्त जीवन व्यतीत करना चाहता है, किसी भी तरह का पारंपरिक, सांस्कृतिक दबाव नहीं लेना चाहता।

यद्यपि व्यक्तिवाद के अतिरिक्त अन्य भी कारण है –

- शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ता प्रवासन
- महिला श्रम की बढ़ती भागीदारी
- सहिष्णुता व लगाव की कमी

विवाह व्यवस्था में परिवर्तन, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, सामाजिक गतिशीलता, जनांकिकीय, आवास की समस्या आदि कारणों को भी लिखें।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

- बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति

उपरोक्त सभी कारणों से एकल परिवार को बढ़ावा मिलता है, जो वृद्धजन समस्या, बचपन में अलगाव व तनाव की भावना जैसी विरल समस्याओं को जन्म देता है।

3½

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0·25	[illegible]	1	0·25		0·25	—
Grade	B	C	C	C	α	B	—

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

16. यह माना जाता है कि विमुद्रीकरण नकदी-विहीन समाज को प्रेरणा देकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की विफलताओं की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

It is believed that the demonetization will provide thrust to the welfare programmes by providing stimulus to cashless society. Discuss this statement in the backdrop of failures of various welfare programmes. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Ans → भ्रष्टाचार, काला धन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से किए गए विमुद्रीकरण का एक बड़ा परिणाम है- नकदी विहीन समाज की प्रेरणा। वस्तुतः इससे कई लाभ देखने को मिलेंगे

- अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्कुलेशन रहेगा
- कागज आधारित मुद्रा छापने में होने वाले खर्चों में कमी आएगी, ये सभी पैसे जनकल्याण में खर्च हो सकेंगे।
- सरकारी योजनाओं का डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकेगा।
- आर्थिक समावेशन होगा।
- काला धन लगाम, कर राजस्व वृद्धि से सरकार का राजकोषीय घाटा कम होगा, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि होगी।

पहले कल्याणकारी कार्यक्रमों की असफलताओं के कारणों की चर्चा करें

- निधि का रिसाव
- आभासी लाभार्थियों का उपस्थिति

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

यद्यपि कुछ विफलताएं व चुनौतियां हैं —

- अवसंरचना की कमी
- डिजिटल शिक्षा की कमी
- इंटरनेट कनेक्शन व स्पीड का वहनीय न होना
- साइबर असुरक्षा - हाल में कई साइबर फ्रॉड देखने को मिले।

यद्यपि सरकार द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में कई प्रयास किए जा रहे हैं — भीम रुप
- डिजीपाठशाला
- फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क
- साइबर सुरक्षा, CERT-IN निर्माण

(5)

डिजिटाइजेशन व कैशलेस सोसाइटी के माध्यम से देश का सतत, तीव्र, समावेशी विकास सम्भव हो सकेगा, इसी पथ पर आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की परिकल्पना पूर्ण की जा सकेगी।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान मे कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1 1/2	1 1/2	0.25	——	0.25	
Grade	B	B	c	C	x	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

18. किसानों की कृषि ऋण माफी केवल अस्थायी राहत है। उक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Waiving off farm loans is only temporary relief to the farmers. Critically examine above statement and give your suggestions for improving conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Ans हाल में कृषि ऋण के बड़े स्तर पर माफी ने पुनः यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या यह कदम कृषक समस्या का स्थायी समाधान है—

हाल ही में आंकड़ों को देखे तो मौसम अनियमितता, फसल बर्बादी, आपदा आदि कारणों से कृषक ऋण पुनर्वापसी में असमर्थ हो जाते हैं, जिस कारण वे बड़े स्तर पर आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं अतः इन आत्महत्याओं को रोकने हेतु कृषक ऋण माफी अपेक्षित है। परन्तु इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ आलोचनाएं भी दिखती हैं —

- सरकार पर बढ़ता राजस्व घाटा बोझ
- वोट बैंक राजनीति
- लाभ बड़े कृषकों द्वारा लिया जाना व छोटे कृषक अभी भी वंचित
- कृषि समस्या का अस्थायी समाधान

सकारात्मक पक्ष को लिखें ॥ सरकार पर विश्वास बढ़ेगा।

अन्य नकारात्मक पक्षों को भी लिखें — राजकोषीय घाटे में वृद्धि

अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित होंगे।

जीवन गुणवत्ता में सुधार

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

- कृषकों द्वारा जानबूझकर ऋण न लौटाया जाना
- बैंकिंग नैतिकता का उल्लंघन
- बढ़ते कृषक आंदोलन

उपाय

- कॉरपोरेट फार्मिंग, कान्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा
- अवसंरचनात्मक विकास पे ज्यादा निवेश करना।

अन्य उपायों को लिखें

जैसे →, क्षमता निर्माण का विकास
◦ मॉडल APMC अधिनियम में परिवर्तन

2 1/2

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1	1	0.25			
Grade	B	C	C	C			

Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)

Copyright - Drishti The Vision Foundation